© 23311455
23317729
Fax.: 23316173

Jamiat Ulama-i-Hind
1-BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI-110 002
E-mail : jamiat@vsnl.com URL : www.jamiatulama.org

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية علماء الهند

इज़राइल के राष्ट्रपति के आगमन के विरोध में धरना प्रदर्शन

स्थानः जन्तर मन्तर, 18 नवम्बर 2016

भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन / प्रेस स्टेटमेंट

आदर्णीय महोदय!

हम आतंकवादी देश इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन की भारत बुलाए जाने और उनके स्वागत की निंदा करते हैं। हिन्दुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीनी काज़ का समर्थन किया है तथा इजराईली आक्रामकता, आतंक, अत्याचार व मानव अधिकारों के हनन के शिकार फिलिस्तीनियों के साथ सहानुभूति व्यक्त की है । दशकों से हमारे देश की विदेश नीति मानवाधिकार संरक्षण और विश्व शांति के समर्थन में रही है, लेकिन इन दिनों यह विचलन की राह पर जा रही है। हम लोकतातित्रक भारत के नागरिक अपनी सरकार के इस नीति परिवर्तन को पूरी तरह से गलत और देश की प्राचीन सभ्यता और परम्प्राओं के खिलाफ मानते हुए खारिज करते हैं।

इजराइल से भारत के राजनयिक संबंध पच्चीस साल पहले शांति के प्रयास के रूप में स्थापित किये गये थे, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी जनता को न्याय दिलाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। लेकिन इससे फिलीस्तीनी जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचा हालांकि इजरायल ऐसे कदमों से ऊर्जा पाकर विश्व शक्तियों से संबंध स्थापित करने में सफल हो गया, यह शक्तियां भी फिलिस्तीन में जारी मानवता विरोधी अत्याचारों में लिप्त हैं 1992 के बाद से भारत और इजराइल के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सेन्य सामग्री, शिक्षा और सांस्कृ तिक क्षेत्रों सहित सभी मैदानों में संबंधों में वृद्धि हुई लेकिन फिलिस्तीनी जनता शांति और न्याय की स्थापना से अब तक कोसों दूर हैं।

हमारा यह मानना है कि इसराइल और भारत के बीच संबंधों में कोई बात खुश होने और जश्न मनाने का नहीं है। न तो फिलीस्तीनी जनता के लिए और न ही उन भारतीय नागरिकों के लिए जो लोकतंत्र, शांति और मानवाधिकार समर्थक हैं। भारत सरकार यहां के मावता प्रिय लोगों के बहुमत के मत और सोच के खिलाफ इजरायल के अलोकतांत्रिक और पूरी तरह से जातिवादी सरकार के हाथ में हाथ डाल कर चलने की कोशिश कर रही है।

हम इसराइल के राष्ट्रपति सेंट आर एवलिन के भारत आगमन को जिसका उद्देश्य भारत इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत करना है, इसलिए भी अस्वीकार करते हैं क्योंकि यह इसराइल द्वारा लगातार अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के समर्थन के बराबर है। इजराइल ने अपने घृणित चरित्र और कार्रवाई से अरब जगत को अशांति का क्षेत्र बना दिया है और बडी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके घरों से निकाल कर और उनकी बस्तियों को नष्ट कर के शरणार्थी जीवन जीने पर मजबूर कर रखा है, इसके अलावा 1967 के बाद से अवैध रूप से क़ब्ज़ा लेकर गाजा और पश्चिमी तट की जनता पर हर तरह के अत्याचार को अपना रखा है।

हम भारत के शान्ति प्रिय नागरिक मस्जिदे अक़सा और दीवार बुराक़ पर मुसलमानों का सर्वोच्च अधिकार स्वीकार करने के संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को के फैसले का स्वागत करते है। मस्जिदे अक़सा मुसलमानों का पहला क़िबला है और बहुत ही सम्मानित मस्जिद है। इसलिए इसका सम्बंध केवल फिलिस्तीन से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मजलूम फिलिस्तीनियों के पक्ष में कई फैसले दिए हैं, लेकिन यह बहुत ही निंदनीय है कि इज़राइल अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों का लगातार अपमान और उल्लंघन करता रहा है और विभिन्न तरीक़ों से फिलीस्तीनी बच्चों, महिलाओं और निर्बलों की हत्या करता रहा है। ऐसा लगता है कि इज़राइल अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार चार्टर की कोई परवाह नहीं है।

© 23311455
23317729
Fax. : 23316173

Jamiat Ulama-i-Hind
1-BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI-110 002
E-mail : jamiat@vsnl.com URL : www.jamiatulama.org

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جمعية علماء الهند

आदर्णीय राष्ट्रपति जी!

अतः हम आप के माध्यम से विश्व समुदाय, मुस्लिम जगत और संयुक्त राष्ट्र से मांग करते है कि

1. पूरी तरह संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए हस्तक्षेप करें, ताकि विस्थापित फिलीस्तीनियों के पुनर्वास और अपने घरों को वापसी का मार्ग खुले तथा इज़राइल को मजबूर किया जाए कि वह अरब अधिकृत क्षेत्रों को ख़ाली कर दे और अपने विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे।
2. गाज़ा की नाकाबंदी तुरंत समाप्त की जाए अगर विश्व समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को इज़राइल पालन नहीं करता और वह अंतरराष्ट्रीय मांग के बावजूद नाकाबंदी जारी रख कर लाखों मनुष्यों को क़ैद का जीवन जीने पर मजबूर कर रहा है, तो इज़राइल को एक आतंकवादी देश घोषित करने का प्रस्ताव लाया जाए और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किये जाएं।
3. अब जबकि मस्जिद अक़सा पर मुसलमानों के क़ानूनी अधिकार का फैसला हो गया है, तो उस पर से इज़राइल अपना अवैध क़ब्जा तुरंत हटाए और ओस्लो समझौते के अनुसार पूरे येरोशलम शहर का नियंत्रण फिलिस्तीनियों के हवाले करे।
4. हम फिलिस्तीन के सम्बंध में भारत की मौजूदा केंद्र सरकार की विमुखता को भारत की चिर स्थापित नीति से विचलन के रूप में देखते है। भारत ने हमेशा फिलिस्तीनियों के संघर्ष और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की हर मंच पर खुल कर समर्थन किया है। हालांकि हाल ही में यूनेस्को में क़िबला अव्वल के संबंध में हुए मतदान से भारत की जान बूझ कर अनुपस्थिति तथा सर्जिकल स्ट्राईक को फिलिस्तीनियों पर इज़राईल के क्रूर हमलों से तुलना पर हम चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि वह महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों की राह पर चलते हुए क्रूर और विस्तारवादी इज़राइल से अपने सम्बंधों में संशोधन करे और दुनिया भर में पीड़ितों के प्रति भारत की मित्रता की परंपरा का उल्लंघन न करे।

समर्थकः

संगठन	प्रतिनिधी	हस्ताक्षर
जमीयत उलेमा–ए–हिंद	मौलाना कारी सैयद मो0 उस्मान मंसूरपुरी, अध्यक्ष	
	मौलाना महमूद मदनी, महासचिव	
जमाअते इस्लामी–ए–हिन्द	मौलाना इनामुर्रहमान	
ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत		
अनहद	मोहतरमा शबनम हाशमी	
	डा0 ज़फ़रूल इस्लाम खान	
जामा मस्जिद युनाइटेड फोरम	मौलाना सैयद तारिक बुखारी	
ए.आ.ई.यू.डी.एफ	मौलाना बदरुद्दीन अजमल, अध्यक्ष	
जामिया क्लेक्टीव		

23311455
23317729
Fax. : 23316173

Jamiat Ulama-i-Hind
1-BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI-110 002
E-mail : jamiat@vsnl.com URL : www.jamiatulama.org

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية علماء الهند

आल इंडिया इंसाफ पार्टी दिल्ली		
मेवात विकास सभा		
मेवात कारवां		
शोल्डर टू शोल्डर		
फिलिस्तीन सोलिडारिटी ओर्गेनाईजेशन		

प्रतिलिपिः–

सेवा में
विदेश मंत्री भारत सरकार,
नई दिल्ली